P.G. II Sem Topic 18-20

DEMONETISATION
(विमुद्रीकरण)

Page No.-1

Dr [illegible]
H.O.D. [illegible]
[illegible]

What is Demonetisation

यह विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की सरकार द्वारा देश की किसी मुद्रा को कानूनी तौर पर [illegible] का [illegible]

विमुद्रीकरण के कारण : (1) [illegible] के बाद नोटों के [illegible] कुछ वर्षों में [illegible] परिवर्तन करना पड़ता : [illegible] के द्वारा [illegible] [illegible] करना है [illegible] बदलना पड़ता है तथा कई [illegible] नोटों का [illegible] किए जाते [illegible] जाते हैं कि कुछ वर्षों में नोटों [illegible]

(2) **जाली नोटों का मामला** : [illegible] के [illegible] 500 और 1000 को [illegible] करने के लिए पाकिस्तान के [illegible] के बड़े नोट यहाँ [illegible] तैयार करवाते थे। [illegible] नोट [illegible] के उसी मिल में बने [illegible] के लिए [illegible] नोटों को [illegible] में पहुँचाने के लिए [illegible] मदद करते हैं।

भारत सरकार ने 8 नवम्बर 2016 को 500 तथा 1000 [illegible] दोनों बड़े [illegible] नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया [illegible] दोनों कोई भी नोट अपनी [illegible] 30 दिसम्बर 2016 तक बैंकों में जमा [illegible] [illegible] की [illegible] 24 [illegible] निकासी [illegible] 35 [illegible] नियंत्रण लगाया गया।

भारत में कब-कब हुई नोटबंदी : भारत में पहली बार 1946 में 500, 1000 और 10000 (दस हजार) के नोटों [illegible] [illegible] में जो प्रचलन था [illegible] की [illegible] कमेटी ने विमुद्रीकरण का [illegible] [illegible] प्रभाव के [illegible] विमुद्रीकरण नहीं [illegible] 1978 में मोरारजी देसाई के [illegible] 1000, 5000 और 10000 के नोट बंद [illegible] के गवर्नर आई. जी. पटेल ने [illegible] 37 [illegible]

कई बार [illegible] पुराने नोटों को [illegible] धीरे-धीरे बंद करती है 2005 में [illegible] 2005 से पहले नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया।

विमुद्रीकरण के उद्देश्य : विमुद्रीकरण के [illegible]

(1) काली अर्थव्यवस्था को खत्म करना अर्थात् काले [illegible] [illegible]
(2) आतंकवादियों तथा तस्करों द्वारा [illegible] के नोटों के प्रयोग [illegible]
(3) जाली नोटों पर रोक, तथा भ्रष्टाचार की [illegible] नियंत्रण।

विमुद्रीकरण के लाभ : (1) **कालेधन पर प्रहार** : [illegible] काली आय के रूप में जमा राशि [illegible] [illegible] की मुद्रा में आय का [illegible] किया [illegible] [illegible] कि पूरा भुगतान किया [illegible] ऐसी व्यवस्था अपनाई [illegible] [illegible] में [illegible] किया [illegible] [illegible] आय से [illegible] के लिए [illegible]

जो नकदी घोषित आय के माध्यम से प्राप्त हुई थी लेकिन उसे बैंकों में जमा नहीं कराते थे और उसके बदले नए नोटों के रूप में जारी नई मुद्रा प्राप्त कर सकते थे। परन्तु जिसके पास काले धन के रूप में मुद्रा थी उसके पास तीन विकल्प थे (1) पहला वे अघोषित मुद्रा राशि की घोषणा करें तथा उस पर जुर्माने की दर से राशि का भुगतान करें अथवा (2) काली आय को छुपाए रखें परन्तु इसका अर्थ होता है कि यह 100 प्रतिशत हो जाती, आयकर विभाग के माध्यम से पुराने नोटों के बदले नए नोट प्राप्त कर सकते थे।

(2) **सरकार को धन का हस्तांतरण**: विमुद्रीकरण के माध्यम से सरकार से जमा धन राशि का हस्तांतरण जमाकर्ताओं से सरकार को हो सकता है, इस रूप में प्राप्त हस्तांतरित आय का प्रयोग सरकार कई उत्पादक उद्देश्यों के लिए कर सकती है - अपने ऋण का भुगतान कर सकती है, बैंकों के पुनः पूंजीकरण में सहयोग कर सकती है और यहाँ तक कि इसका पुनः वितरण सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कर सकती है।

(3) विमुद्रीकरण को सरकार से जनता को कर पालन के लिए विवश करने का हथियार माना जा सकता है। भारत सरकार के द्वारा 2016-17 के अनुसार यह सरकार जनता को ही आगे भी स्पष्ट चेतावनी है कि वह करों के भुगतान के लिए दृढ़ है तथा अब करदाताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

(4) **Digitisation** - विमुद्रीकरण का एक लाभ यह भी होगा कि नकद के रूप आदान प्रदान कम होगा तथा लोग इंटरनेट, मोबाईल या बैंकों के क्रेडिट डेबिट कार्डों से अधिक भुगतान करेंगे। इससे बैंकिंग के माध्यम से लेन-देन का लेखा जोखा पता रहेगा। परन्तु नगदी भुगतान करने वालों का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है इसलिए चोरी की संभावना अधिक रहती है।

(5) **भूमि संपत्ति के क्रय-विक्रय पर प्रभाव**: विमुद्रीकरण का भूमि व भवन आदि के क्रय विक्रय पर सीधा तथा प्रभावशाली प्रभाव होने की संभावना है क्योंकि इस क्षेत्र में क्रय विक्रय में काले धन का काफी हिस्सा होता है तथा प्रत्येक सौदे में एक बड़े राशि का भुगतान काले धन के रूप में किया जाता है। विमुद्रीकरण से जिस हद तक काले धन का प्रयोग कम होगा और जिस हद तक अधिकतम लेन-देन में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से होगा तो उस हद तक इस तरह की कर चोरी पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

विमुद्रीकरण के नुकसान इसके दोष: (1) **असुविधा और आर्थिक उथल-पुथल**: ऐसा माना जाता है कि नकद लेन-देन से भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती बनी रही है। विमुद्रीकरण के कारण आर्थिक उथल-पुथल आई। बैंकों के आगे लोग घंटों तक खड़े रहने के लिए मजबूर रहे। लाखों लोगों का रोजगार बंद हो गया। Consumer Expenditure में काफी गिरावट आई।

2) **काले-धन सम्बन्धी पर कोई खास असर नहीं**: विमुद्रीकरण के कारण जो आम जनता में उत्साह दिखाई पड़ा कि जनता को विश्वास था कि काले-धन की वापसी होगी। परन्तु ऐसा

कुछ नहीं हुआ क्योंकि काले धन के मालिकों ने [illegible] अपनाए और अपने काले धन को सफेद करने में कामयाब हो गए। [illegible] [illegible] ने भी लाभ लिया [illegible] के [illegible] काले धन के मालिकों के [illegible] नोट बदलने के लिए। काले धन के मालिकों के [illegible] [illegible] विमुद्रीकरण को कोई खास सफलता नहीं मिली।

(3) डिजीटाईजेशन की सीमित गुंजाईश : [illegible] ने [illegible] अनुमान प्रकट किया है कि भारत में [illegible] कार्डों का [illegible] में [illegible] 40 प्रतिशत निष्क्रिय खाते हैं। [illegible] [illegible] कार्यक्रम 2014-16 के बीच प्रधानमंत्री जन-धन योजना के [illegible] 25 करोड़ नए खाते खोले गए। इनमें से भी 6 करोड़ खाते [illegible] [illegible] इन आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे देश में [illegible] [illegible] बैंकिंग प्रणाली से अछूती हैं। इस हालत में डिजीटाईजेशन मुश्किल है।

(4) काली अर्थव्यवस्था पर खास प्रभाव नहीं, [illegible] कुमार के अनुसार [illegible] काले धन को लक्ष्य मान रही थी वह देश में मौजूद काले धन का मात्र 1 प्रतिशत था। 2016 में [illegible] काले धन का [illegible] 3.5 प्रतिशत है। यदि सरकार इसी तरह अपने उद्देश्य में सफल हो भी जाती तो काली अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इस बात की भी जानकारी है कि जिन बड़े लोगों ने बड़ी मात्रा में काले धन को इकट्ठा किया है उनका बड़ा हिस्सा या तो वे विदेशों में [illegible] रखा है या [illegible] सोने या रत्नों के रूप में रखा है।

(5) विमुद्रीकरण से आतंकवाद पर रोक संभव नहीं : जिस समय सरकार ने विमुद्रीकरण किया था उस समय इस बात को यही बताया गया था कि इस योजना से जाली नोटों की समस्या का समाधान हो जाएगा। परन्तु जैसा कि पूर्व ई. एस. मिस्त्री का कथन है कि जाली नोटों की संख्या परिचालन में मुद्रा राशि का बहुत छोटा अंश है - केवल 400 करोड़ रुपये इतना ही नहीं। [illegible] [illegible] पुरानी [illegible] नकली नोट बन रहा था तो नई की भी बनाई जा सकती।

(6) पर्यटन उद्योग को काफी धक्का लगा, तथा [illegible] G.D.P. पर भी असर पड़ा।

विमुद्रीकरण के आर्थिक प्रभाव : (1) संवृद्धि और मुद्रा स्फीति पर प्रभाव : अक्टूबर 2016 में रिजर्व बैंक ने 2016-17 के लिए [illegible] value Added में वृद्धि का अनुमान 7.6 प्रतिशत लगाया था। दिसम्बर 16 में कम करके 7.1 प्रतिशत तथा 8 फरवरी 2017 को 6.9 प्रतिशत पर [illegible] संवृद्धि अनुमानों को कम करने के पीछे कारण यह था कि यद्यपि कुछ [illegible] [illegible] क्षेत्र तो विमुद्रीकरण के प्रतिकूल प्रभावों से बचा रहा तथापि कुछ विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों पर विमुद्रीकरण का बुरा असर पड़ा।

2) वित्तीय क्षेत्र! विमुद्रीकरण का प्रभाव बैंक के Balance Sheet पर Liquidity पर मौद्रिक नीति के संचारण पर, और -

कैश आधारित व्यवसायों, संस्थाओं पर तथा भ्रष्टाचार जैसी बातों पर भी असर हुआ। विमुद्रीकरण के कारण [illegible] से [illegible] और बैंक खातों में जमा पूंजी [illegible] में तेज वृद्धि हुई [illegible] होने वाली [illegible] राशि [illegible] से [illegible] के ब्याज दरों में [illegible] में कमी आई और [illegible] जमा राशि पर [illegible] वाली [illegible] प्रक्रियाओं पर [illegible] गिरावट हुई [illegible] राशि पर [illegible] लोगों का [illegible] Fund के प्रति लोगों का [illegible] और लोगों ने [illegible] निवेश करना शुरू कर दिया।

(3) वित्तीय बाजार: विमुद्रीकरण से वित्तीय बाजार के [illegible] को प्रभावित किया विमुद्रीकरण के कारण [illegible] में [illegible] आई उसके परिणामस्वरूप सरकारी प्रतिभूतियों के प्रति [illegible] कमी आई।

(4) विदेशी क्षेत्र: देश के लगभग 3 करोड़ 60 लाख अति लघु तथा मध्यम उद्यम आयात का लगभग 40 प्रतिशत निर्यात [illegible] करते हैं और 8 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। इनमें से बहुत से [illegible] और आभूषण उद्योग, कालीन उद्योग, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, हस्तशिल्प व [illegible] उद्योग इत्यादि में कार्यरत हैं। विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप नकदी की कमी आई- इससे इन उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। बहुत से [illegible] श्रमिकों को वेतन भुगतान नहीं कर पाए अर्थात [illegible] उत्पादन में गिरावट हुई तथा रत्न और आभूषण [illegible] व [illegible] उद्योगों के निर्यात [illegible] कम हो गए था। फिर [illegible] के आयातों पर [illegible] नवम्बर 2016 में स्वर्ण [illegible] में तेज वृद्धि दिखाई दी क्योंकि बहुत से लोगों ने [illegible] मात्रा में अपने काले धन को सफेद करने हेतु स्वर्ण खरीदने का प्रयास किया।

(5) भुगतान के डिजिटल तरीके: विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप भुगतान के डिजिटल तरीकों में तेज वृद्धि हुई। भारत सरकार ने तथा रिजर्व बैंक ने डिजिटल तरीकों से भुगतानों को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। डेबिट तथा क्रेडिट कार्डों के माध्यम से खरीददारी को प्रोत्साहित किया गया। डिजिटल लेन-देन पर का लाभ उपलब्ध कराए गए, नए डिजिटल माध्यमों को शुरू किया गया तथा उपलब्ध डिजिटल माध्यमों का और प्रसार किया गया।